

[2008] 10 एस.सी.आर. 195

कपिला हिंगोरानी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य

(रिट याचिका (सिविल संख्या 488, सन् 2002 में 2007 का आई.ए. संख्या 21)

8 जुलाई, 2008

[एस.बी. सिन्हा और वीएस. सिरपुरकर जे.जे.]

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 - धारा 65 और 85 - मूल बिहार राज्य का मौजूदा बिहार राज्य और झारखंड राज्य में विभाजन - बिहार हिल एरिया लिफ्ट इरीगेशन इरीगेशन कॉरपोरेशन -(भालको) झारखंड राज्य में कार्यरत - झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरीगेशन कॉरपोरेशन-(झालको) का गठन - कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करना - सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका - कर्मचारियों के वेतन की देनदारी को पूरा करने के लिए बिहार राज्य को निर्देश - इस बीच, झालको द्वारा तत्कालीन भालको के कर्मचारियों के अवशोषण के लिए विज्ञापन इस शर्त के साथ कि ऐसे कर्मचारी अपने पहले के दावे को छोड़ देंगे - 389 आवेदनों में से, केवल 302 कर्मचारी पात्र पाए गए और अवशोषित हुए - अंतरिम आवेदन - आदेश दिनांक 13.1.2005 द्वारा, भालको के कर्मचारियों के अवशोषण के लिए निर्देश जारी किए गए जिन्होंने इस स्तर पर बिना किसी किसी उपक्रम के रोजगार का विकल्प चुना था - गैर-अनुपालन - अंतरिम आवेदनों पर धारित किया गया: आदेश दिनांक 13.01.2005 को अवमानना कार्यवाही शुरू करके लागू किया जाना चाहिए था - गलत बयान के आधार पर इसकी शुरुआत और दोषी अधिकारियों अधिकारियों की सजा से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इस प्रकार ऐसा नहीं किया गया - झारखंड उच्च न्यायालय में पिछले वेतन के साथ - साथ अवशोषण का दावा करने वाले कर्मचारियों द्वारा रिट याचिका की लंबितता को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया - यह अंतिम अवशोषण, पिछले वेतन और उसके भुगतान करने के दायित्व के प्रश्न का निर्धारण करेगा।

बिहार के मूल राज्य को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के द्वारा मौजूदा राज्य और झारखंड राज्य में विभाजित किया गया था। इसके बाद, बिहार हिल एरिया लिफ्ट इरीगेशन कॉरपोरेशन-(भालको) का हिस्सा संचालन के लिए झारखंड की सीमा में आता था। झारखंड राज्य ने 29.12.2001 से झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरीगेशन कॉरपोरेशन-झालको का गठन किया। यह कथन किया गया था कि उक्त निगम के

कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन का भुगतान नहीं किया गया , जिससे कर्मचारियों की भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक जनहित याचिका दायर की गई। 09.05.2003 को इस न्यायालय ने राज्य निगम के कर्मचारियों के वेतन की देनदारी को पूरा करने के लिए बिहार राज्य के खिलाफ अंतरिम निर्देश जारी किया और केंद्र सरकार को संपत्ति और देनदारियों के विभाजन के संबंध में निर्णय लेने का भी निर्देश दिया। उच्च न्यायालय को बिहार राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण वाली सरकारी कंपनियों के संबंध में सभी परिसमापन कार्यवाही का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। इस बीच , 27.3.2003 और 31.7.2003 को JHALCO ने भालको के पूर्व कर्मचारियों / कर्मकारों के अवशोषण के लिए विज्ञापन जारी किया, जो इस शर्त के अधीन था कि ऐसे कर्मचारियों को अवैतनिक वेतन के अपने पहले के दावों को छोड़ना होगा। भालको के कर्मचारियों द्वारा रोजगार के लिए 398 आवेदन दायर किए गए थे, जिनमें से 302 को योग्य पाया गया और समाहित कर लिया गया। 13.8.2004 को, इस न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य पुनर्गठन अधिनियम , 2000 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनियों / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संपत्तियों और देनदारियों के विभाजन के संबंध में निर्णय लेने के निर्देश जारी किए। इसके बाद आई .ए. दाखिल किए गए। 13.1.2005 को, इस न्यायालय ने भालको के उन कर्मचारियों को समाहित करने का आदेश पारित किया, जिन्होंने इस स्तर पर बिना किसी उपक्रम के रोजगार का विकल्प चुना था और आई .ए. का निपटारा कर दिया गया था। आई .ए. क्रमांक 11/2005 एवं आई.ए. क्रमांक 13/2005 दिनांक 13.1.2005 के आदेश में संशोधन / स्पष्टीकरण हेतु दाखिल किये गये थे। झारखंड को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया। झारखंड राज्य ने तर्क दिया कि दिनांक 13.1.2005 के आदेश के अनुसार , 398 कर्मकार भालको को तीन सप्ताह के भीतर ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था , लेकिन केवल 302 ही आए और काम पर लग गए , हालांकि 158 कर्मचारी अधिशेष पाए गए। 16.07.2007 को, इस न्यायालय ने उन कर्मचारियों का खर्च वहन करने के लिए राज्य को निर्देश जारी किए जो गंभीर रूप से बीमार थे। झारखंड राज्य के अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान के बाद , अदालत ने माना कि जो लोग नियत दिन पर ड्यूटी पर नहीं आए , उन्हें शामिल करने के संबंध में कोई निर्देश पारित नहीं किया जाएगा और आई .ए. नंबर 11/2005 का निपटारा कर दिया जाएगा।

यह प्रस्तुत किया गया कि यह कथन सही नहीं है क्योंकि पूर्ववर्ती वाद को कर्मचारियों के अवशोषण के लिए विज्ञापन न्यायालय के आदेश दिनांक 13.1.2005 से बहुत पहले जारी किए गए थे और दिनांक 13.1.2005 के आदेश के अनुसार , कर्मचारियों

द्वारा केवल 216 नए आवेदन दायर किए गए थे। पूर्ववर्ती भालको एवं झालको ने इसे स्वीकार कर ठंडे बस्ते में डाल दिया। दिनांक 21.9.2007 को न्यायालय ने राज्य को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इसलिए , अपीलकर्ता ने वर्तमान आई .ए. 21/2007 दायर किया। क्रमांक में प्रतिवादी राज्य / झालको को दिनांक 13.1.2005 के आदेश के अनुसार झालको में 213 कर्मचारियों के अवशोषण आदेश पारित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। इसके बाद , 13.12.2007 को, इस न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि उसकी राय थी कि बिहार राज्य और झारखंड राज्य के सचिवों के साथ-साथ भालको और झालको के प्रबंध निदेशकों को भी कर्मचारियों के अवशोषण के संबंध में बातचीत करनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार के उपयुक्त विभाग का हस्तक्षेप भी लिया जा सकता है। जब मामला उठाया गया , तो झारखंड राज्य ने बिना शर्त माफी मांगी कि 13.1.2005 के आदेश के बाद दायर किए गए पहले के हलफनामों में दिखाई गई स्थिति रिपोर्ट वास्तव में 13.1.2005 से पहले की अवधि की थी, हालांकि यह कथित तौर पर बाद की अवधि से संबंधित बताया गया था।

कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए धारित किया:

1.1 आई.ए. 11 के अनुसरण में रिपोर्ट दाखिल करने में और इस न्यायालय के समक्ष गंभीर बयान देते हुए कि इस न्यायालय के दिनांक 13.1.2005 के आदेश के अनुसरण में 302 कर्मचारियों को पहले ही समायोजित कर दिया गया था , एक स्पष्ट से भ्रामक और गलत बयान दिया गया था , जिसके लिए यह न्यायालय आई.ए. नंबर 11 में आदेश दिनांक 16.7.2007 पारित नहीं करता। घबराहट व्यक्त की जाती है। झारखंड राज्य द्वारा मांगी गयी माफी संतोषजनक नहीं है। इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है राज्य सरकार की ओर से उसके स्थायी अधिवक्ता द्वारा ऐसा बयान कैसे जारी किया यह स्पष्ट है कि राज्य ने स्वयं को कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने का केवल एक घटिया प्रयास किया।[पैरा 14] [211 जी 212 बी]

1.2. झारखंड राज्य और झालको की ओर से दो हलफनामे बताते हैं कि झालको और राज्य समय-समय पर अपना रुख बदल रहे हैं। उनके रुख कई बार विरोधाभासी और और समझ से बाहर हो गए हैं। कैबिनेट नोट दिनांक 9.1.2002 जो रिट याचिकाकर्ता द्वारा आई.ए. 11 सन् 2005 के साथ दायर किया गया था स्पष्ट रूप से सुझाव देता है झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी कि भालको को झालको के रूप में चलाया जाना चाहिए। 2003 में, झालको ने भालको कर्मचारियों के अवशोषण के लिए दो विज्ञापन

विज्ञापन दिए और बाद में भी यह स्वीकार किया गया कि झालको को भालको के अनुभवी अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता है। इन विज्ञापनों के अनुसरण में , भालको के सभी कर्मचारी नियमित होने के लिए आवेदन कर सकते थे, बशर्ते कि उनके आवेदन सही पाए गए हों। तदनुसार , लगभग 302 कर्मचारियों को शामिल किया गया। दूसरों के आवेदन अस्वीकार कर दिए गए और कुछ अन्य ने आवेदन ही नहीं किया था , शायद इस शर्त के कारण कि ऐसे कर्मचारियों को अवैतनिक वेतन के अपने पहले के दावों को छोड़ना पड़ा। जिस समय विज्ञापन जारी किए गए थे उस समय सभी कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए किसी भी न्यायालय के आदेश के माध्यम से कोई बाध्यता नहीं थी और यह केवल एक मानवीय विचार हो सकता था जिससे उक्त विज्ञापन जारी किए गए। यह नहीं भुलाया जा सकता कि कोई नहीं था कि झालको के पास प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हैं, इसलिए झालको को भालको के अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता है। इसलिए , यह कदम केवल BHALCO के नामकरण को बदलने और JHALCO के समान जारी रखने के लिए लिए था। [पैरा 18] [216ए-217ए]

1.3 ऐसा प्रतीत होता है कि इन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न होना कर्मचारी एक गैर-कारक था और इसलिए, झालको दोहरा लाभ उठाना चाहता था , अर्थात् सबसे पहले यह सारे अनुभवी कर्मचारी प्राप्त कर सकता था और दूसरा, यह भी कि उनके वेतन भुगतान की देनदारी के दायित्व का सामना किए बिना यह याद रखना चाहिए कि यह सब इसी न्यायालय के आदेश दिनांक 9.5.2003 के मद्देनजर था , जिसमें इस न्यायालय ने बिहार राज्य से 50 करोड़ रुपये की राशि निगम के कर्मचारियों को वेतन के वितरण के लिए जमा करने को कहा गया तथा तदर्थ रूप से जरूरतमंद कर्मचारियों को धनराशि का भुगतान करने के लिए भी निर्देश दिया था। न्यायालय ने कंपनी की संपत्तियों संपत्तियों और देनदारियों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का भी निर्देश दिया था। इसलिए जब 7.8.2003 की कट-ऑफ तिथि के साथ, विज्ञापन जारी किए गए झालको का एक अलग फ़ायदा था। हालाँकि , उसके बाद , इस न्यायालय का आदेश दिनांक 13.1.2005 आया, जिसमें, इस न्यायालय ने निर्देशित किया कि JHALCO के अस्तित्व में आने और आगे निर्देशित होने के समय जिन संबंधित कर्मचारियों को समाहित किया जाना जाना था, उन्हें अपने पिछले अवैतनिक वेतन के लिए दावों को त्यागने का वचन देने की आवश्यकता नहीं है। तब तक न्यायालय के आदेश दिनांक 13.1.2005 की भाषा से ऐसा लगता है कि अवशोषण के लिए कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया गया। संभवतः, संभवतः, इसलिए इस न्यायालय ने ऐसे कर्मचारियों को छह सप्ताह का समय दिया है। फिर से जैसे पहले के विज्ञापनों में केवल अपने पूर्व के वेतन के दावे का त्याग करने वाले

वाले कर्मचारी ही आवेदन कर सकते थे, सभी कर्मचारियों ने आवेदन नहीं किया और यह संख्या 302 पर सीमित हो गई। अब, आदेश दिनांक 13.1.2005 के अनुसरण में, 216 और कर्मचारियों ने आवेदन किया था और वह भी अपने पूर्व वेतन के दावों को त्यागने की बिना किसी पूर्व सूचना के। शायद इसकी वजह यह है कि दिनांक 8.8.2005 की बैठक बैठक में JHALCO की वित्तीय स्थिति को कम करने के लिए और कर्मचारियों की कुल संख्या 214 तक सीमित करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था। वास्तव में, यदि अतिरिक्त शपथ पत्र के पैराग्राफ ए (एफ) को देखा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यद्यपि कि 152 अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, फिर भी 64 अधिकारियों की आवश्यकता थी - क्योंकि 78 अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या के मुकाबले केवल 14 अधिकारी कार्यरत थे। कर्मचारियों को कम करने और कर्मचारियों की कुल संख्या 214 तक सीमित करने की यह कवायद इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.1.2005 के मद्देनजर एक जानबूझकर की गई कवायद प्रतीत होती है, और संयोगवश, उस आदेश भी उसकी वास्तविक भावना से पालन नहीं किया गया, जिसके कारण अंततः याचिकाकर्ताओं को आईए. 11 दाखिल करने की आवश्यकता पड़ी। अतिरिक्त शपथ पत्र के पैराग्राफ में दिए गए आंकड़े भी भ्रामक हैं। यदि ठीक से गणना की जाए तो कुल स्वीकृत संख्या 214 के मुकाबले 302 कर्मचारी कार्यरत थे। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि केवल 88 अतिरिक्त कर्मचारी कार्यरत थे और वह भी दिनांक 8.8.2005 के निर्णय से पहले। इस प्रकार पूर्व में 152 अतिरिक्त कर्मचारियों का आंकड़ा स्पष्ट रूप से भ्रामक था। इस प्रकार JHALCO द्वारा कर्मचारियों की कटौती को उचित ठहराने के लिए न तो कोई स्पष्टीकरण है, न ही कोई आँकड़े। आखिरकार क्षेत्र या गतिविधियों में कोई कटौती नहीं की गई, कम से कम किसी की ओर से कोई अभिवचन नहीं किया गया। ऐसे में JHALCO के कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने का निर्णय उचित, तार्किक अथवा युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है और यह केवल इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 13.01.2005 से बचने का प्रयास दर्शित होता है। [पैरा 18] [217-ए-218-डी]

1.4 वित्त की बहुत बड़ी समस्या है। अतिरिक्त हलफनामा में यह कथन किया गया है कि JHALCO वर्ष 2005-06 तक 3.16 करोड़ रुपये के घाटे में चलाया गया था। इसका वार्षिक वेतन आज की तारीख में 3.60 करोड़ हैं और इसने पहले से ही वित्तीय वर्ष 2008-2008-09 के लिए भुगतान करने के लिए झारखंड राज्य से 2.60 रुपये की मांग की है। हालाँकि हलफनामा उस योगदान के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देता है जो वेतन के बकाया के कारण बिहार राज्य द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। [पैरा 19] [218 ई-एफ]

1.5 जब बिहार राज्य की प्रतिक्रिया देखी जाती है तो बिहार सरकार के सचिव द्वारा झारखंड सरकार के सचिव को दिनांक 22.1.2001 के पत्र द्वारा भालको के सभी कर्मचारियों को बिना किसी शर्त के झालको में समाहित करने की सिफारिश के संदर्भ को छोड़कर कोई और बात प्रतीत नहीं होती है। बिहार राज्य की ओर से लिखित निवेदन के नाम पर, केवल इतना कहा गया है कि चूंकि भालको झारखंड राज्य में स्थित एक निगम था और इसका संचालन क्षेत्र भी झारखंड राज्य में था, इसलिए बिहार पुनर्गठन अधिनियम अधिनियम 2000 की धारा 47 (1) और धारा 56 के अनुसार, भालको अपनी सभी देनदारियों और परिसंपत्तियों के साथ झारखंड सरकार का एक निगम है। बिहार राज्य ने आगे दोहराया कि भालको को बिहार राज्य की संपत्ति मानने का केंद्र सरकार का निर्णय और भालको के परिसमापन के लिए कदम उठाने के लिए दिनांक 13.9.2004 के पत्र के माध्यम से दिया गया निर्देश सही निर्णय नहीं है, और कि उसने इस पर पुनर्विचार करने के लिए पत्र लिखा था। यह आश्चर्य की बात है कि बिहार सरकार द्वारा इतना अड़ियल रुख रुख कैसे अपनाया गया। किसी भी कोण से देखा जाए, तो बिहार राज्य द्वारा इस विशिष्ट दलील पर इस दायित्व से पूरी तरह से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है कि भालको अब झालको बन गया है। यह मुद्दे का अत्यधिक सरलीकरण होगा। यह इस तथ्य से अलग है कि भालको के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में, बिहार के छह जिलों का उल्लेख है जो इसके संचालन क्षेत्र के रूप में बिहार राज्य में बने रहे। दिनांक 13.9.2004 का आदेश देखा गया जो बिहार राज्य पर बाध्यकारी है। उस आदेश के द्वारा, केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि बिहार राज्य सरकार भालको के संबंध में परिसमापन शुरू करेगी। यदि ऐसा है, तो आवश्यक तर्क के अनुसार, बकाया वेतन का भुगतान करने का दायित्व बिहार राज्य का है, जिसे उसे पूरा करना होगा। [पैरा 20] [218 जी-219 ई]

2. दिनांक 13.01.2005 के आदेश को लागू करने का तरीका न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1970 अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करना होगा। ऐसी कार्यवाही, जैसा कि सर्वविदित है अंतिम उपाय के माध्यम से शुरू की जानी चाहिए। केवल इसलिए कि गलत बयान दिया गया था जिसके संबंध में पहले टिप्पणियाँ की गई थीं, उसके लिए दोषी अधिकारियों की शुरुआत और परिणामी सजा, किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा। [पैरा 21] [[219 जी-220 एफ]

3. पिछले वेतन के साथ-साथ अवशोषण का दावा करने वाले कर्मचारियों द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका लंबित है। इसलिए हम अंतिम निर्देश देने से से बचेंगे, इसलिए हम सीधे इस न्यायालय के समक्ष दायर जनहित याचिका में श्रम विवाद

विवाद से निपटना नहीं चाहते हैं। बेहतर होगा कि उक्त रिट याचिका में लंबित सभी प्रश्नों पर यथाशीघ्र अंतिम निर्णय लिया जाए। [पैरा 21] [219-एफ]

सुशीला राजे होल्कर बनाम अनिल काक (सेवानिवृत्त) 2008(7) स्केल 484-संदर्भित।

4.1 झारखंड उच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित रिट याचिका का यथाशीघ्र और, यदि संभव हो तो, तारीख से छह सप्ताह के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया जाता है। यह स्पष्ट किया गया है कि अंतिम अवशोषण , पिछले वेतन और उसका भुगतान करने के लिए ई दायित्व का प्रश्न उक्त रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। [पैरा 22] [220 ए-221 सी]

4.2 प्रबंध निदेशक, भालको और झालको तथा बिहार और झारखंड सरकार के सचिवों को निर्देश दिया जाता है कि वे तारीख से एक महीने के भीतर बैठक करें और देय वेतन के बकाया के संबंध में निर्णय लें और दायित्व का आकलन करें। पहले से ही समाहित और समाहित किए जाने वाले कर्मचारी, और अंतिम निर्णय लेने के लिए निर्णय की तारीख के एक सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय को उसकी रिपोर्ट देंगे। [पैरा 22] [221 सी-डी]

4.3 केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी कि उसके द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2004 के निर्देशों का बिहार राज्य द्वारा अनुपालन जाए। खपैरा 22, ख221 ई-एफ,

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: आई. संख्या 21 सन् 2007

रिट पिटिशन (सिविल संख्या 488 सन् 2002

भारत के अटॉर्नी जनरल (एन.पी.), पी.एस. मिश्रा (ए.सी.), (एन.पी.), अमन इलिंगोरानी प्रिया इलिंगोरानी (मैसर्स हिंगोरानी एंड एसोसिएट्स के लिए), गोपाल सिंह, अनिल के. झा, अनिल के. चोपड़ा, डी.एन. गोबर्धन, संध्या गोस्वामी, सुषमा सूरी, अजीत कुमार सिन्हा, अमिताभ एस. यशोवर्धन, ए. परिमल, सी.डी. सिंह और अमित कुमार पक्षों के लिए उपस्थित।

यह निर्णय माननीय न्यायमूर्ति वी.एस. सिरपुरकर द्वारा सुनाया गया।

1. वर्तमान आवेदन में , याचिकाकर्ता निम्नलिखित पर इस न्यायालय से निर्देश चाहता है:

(ए) प्रत्यर्थी राज्य/ झालको को दिनांक 13.1.2005 के आदेश का तुरंत अनुपालन करने और विभिन्न तिथियों पर एमडी , झालको द्वारा जारी पत्रों में सूचीबद्ध 213 कर्मचारियों के संबंध में झालको में अवशोषण का आदेश पारित करने का निर्देश दें (आई.ए. के साथ संलग्न) दिनांक 13.1.2005 के आदेश के अनुसार जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है उन्हें छोड़ दिया जाए।

(बी) कोई अन्य आदेश पारित करें जो उपयुक्त और उचित समझा जाए।

2. उचित निर्णय हेतु संक्षिप्त इतिहास आवश्यक होगा।

इतिहास:

3. बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 15.11.2000 से मूल राज्य बिहार को मौजूदा बिहार राज्य और झारखंड राज्य में विभाजित किया गया। झारखंड राज्य ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 85 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या 2580 द्वारा “झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन” (इसके बाद ‘झालको’ कहा जाएगा) नामक एक निगम का गठन किया जो 29.12.2001 से प्रभावी हुआ।

4. यह याद किया जा सकता है कि इस निगम के कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन का भुगतान न होने के परिणामस्वरूप भुखमरी की स्थिति होने के संबंध में प्रेस रिपोर्टें थीं। यह भी बताया गया कि बिहार राज्य कृषि -उद्योग विकास निगम के एक कर्मचारी के बेटे चंदन भट्टाचार्य ने आत्मदाह की कोशिश की , जो घटना प्रेस में व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई थी। अंततः , उक्त चंदन भट्टाचार्य ने जलने के कारण दम तोड़ दिया। एक लोक भावना के अधिवक्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में जनहित याचिका दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उक्त स्वामित्व वाले निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और वैधानिक निकाय, के कर्मचारियों को बकाया वेतन के भुगतान के लिए बिहार राज्य सरकार की देनदारी के बारे में सवाल उठाया गया। बिहार राज्य ने अपना जवाबी हलफनामा दायर किया और दावा किया कि वेतन का

का भुगतान वैधानिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था और इसके अलावा 26 उपक्रमों के मामले में 30.9.2002 तक सभी वेतन का भुगतान किया गया था। हालाँकि कुछ अन्य निगमों के संबंध में, यह बताया गया कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया और करोड़ों रुपये का भारी बकाया बना हुआ है। बिहार हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन (जिसे इसके बाद 'भालको' कहा जाएगा) सहित कम से कम 16 उपक्रमों के मामले में, यह भी स्वीकार किया गया कि 14 कर्मचारियों की मृत्यु मृत्यु कार्यस्थल पर और 9 की सेवानिवृत्ति के बाद हुई थी। हालाँकि इस बात से पूरी तरह तरह इनकार किया गया कि निगम के किसी भी कर्मचारी की भूख से मौत या आत्महत्या हुई थी। इस न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी और बिहार राज्य और भारत संघ की ओर से पेश हुए विद्वान वकील को सुनने के बाद और कानून पर विस्तार से विचार करने के बाद, न्यायालय ने 9.5.2003 को मामले में निम्नलिखित अंतरिम निर्देश जारी किए:

(i) उच्च न्यायालय बिहार राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण वाली सरकारी कंपनियों के संबंध में सभी परिसमापन कार्यवाहियों को यथासंभव शीघ्रता से निपटाने का प्रयास कर सकता है। उक्त उद्देश्य और / या उसके सहायक या आकस्मिक उद्देश्यों के यह हो सकता है ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और / या सरकारी कंपनियों से संबंधित संपत्तियों की बिक्री और/ या निपटान के माध्यम से एक अंतरिम आदेश और / या आदेश पारित करना या ऐसे उपाय या उपाय करना जो वह उचित और उचित समझे।

(ii) उपरोक्त उद्देश्यों के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन से अधिक सदस्यों वाली एक समिति नियुक्त की जा सकती है जो कंपनियों की संपत्ति और देनदारियों की जांच कर सकती है और उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट यथाशीघ्र, अधिमानतः समिति के गठन की तारीख से तीन महीने महीने के भीतर प्रस्तुत कर सकती है। उक्त समिति की नियुक्ति के नियम और शर्तें न्यायालय द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। इस संबंध में सभी खर्च बिहार राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।

(iii) उच्च न्यायालय समय-समय पर जब भी उचित समझे, उक्त समिति को अपेक्षित निर्देश दिशा-निर्देश जारी करने का हकदार होगा।

(iv) वर्तमान में राज्य निगमों के कर्मचारियों को वेतन के वितरण के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष 50 करोड़ रुपये की राशि जमा करेगा। 50 करोड़ रुपए की राशि दो किश्तों में जमा कराई जाए। आधी राशि एक महीने के भीतर और शेष राशि उसके एक

महीने के भीतर देय होगी। उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी कंपनियों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संपत्तियों की बिक्री सहित किसी भी स्रोत से जमा जमा की गई और / या अन्यथा प्राप्त राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारी को आनुपातिक रूप से किया जाए जिसके लिए पक्षकार अपने दावे इससे पहले दायर कर सकते हैं।

(v) हालाँकि उच्च न्यायालय अपने विवेक से जरूरतमंद कर्मचारियों को तदर्थ आधार पर कुछ धनराशि वितरित करने का निर्देश दे सकता है ताकि वे कुछ समय के लिए लिए खुद को बनाए रखने में सक्षम हो सकें।

(vi) श्रमिकों के अधिकारों पर कंपनी अधिनियम की धारा 529-ए के अनुसार विचार विचार किया जाएगा ।

(vii) केंद्र सरकार को राज्य पुनर्गठन अधिनियम , 2000 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनियों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संपत्तियों और देनदारियों के विभाजन के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

(viii) झारखंड राज्य को प्रत्यर्थी के रूप में शामिल किया जाता है। नए जोड़े गए प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया जाए।”

यह स्पष्ट है कि ये निर्देश केवल उन अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए थे जो उस समय प्रचलित थीं।

5. ऐसा लगता है कि इसके बाद , कई विकास हुए, जिनमें पटना उच्च न्यायालय द्वारा समिति का गठन, साथ ही 50 करोड़ रुपये का वितरण भी शामिल था जिसे बिहार राज्य द्वारा भुगतान करने का निर्देश दिया गया था और जिसे दिशानिर्देश के अनुसार जमा किया गया था। इस न्यायालय ने 13.8.2004 को एक निर्देश जारी किया , जिसमें राज्य सरकार को संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनियों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संपत्तियों और देनदारियों के विभाजन के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।

6. दो अंतरिम आवेदन आई.ए. नं. 7 सन् 2004 और आईए नं. 9 सन् 2004 दाखिल हुए। आईए नं. 7 सन् 2004 में इस प्रार्थना के साथ झालको के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था कि झालको को 15.11.2000 से झालको का उत्तराधिकारी माना जाना चाहिए। 27.3.2003 और 31.7.2003 को विज्ञापनों के माध्यम से श्रमस्व् द्वारा कथित पेशकश के कारण यह आवश्यक हो गया था। जहां पहले विज्ञापन द्वारा आवेदन

जमा करने की अंतिम तिथि 5.4.2003 थी, वहीं दूसरे विज्ञापन द्वारा इसे बढ़ाकर 7.8.2003 कर दिया गया। 398 आवेदन दायर किए गए थे, जिनमें से 302 पात्र पाए गए और उन आवेदकों को समाहित कर लिया गया। इस प्रकार 14 अधिकारी 44 तृतीय श्रेणी कर्मचारी और 244 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समाहित किये गये। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भालको के कर्मचारियों को झालको द्वारा तभी समाहित किया जाएगा जब वे अपने अवशोषण की तारीख से पहले की अवधि के लिए वेतन का दावा छोड़ देंगे। आईए नं. 9 सन् 2004 में यह निर्देश मांगा गया था कि प्रत्यर्थी राज्य बिहार और / या झारखंड राज्य को पटना उच्च न्यायालय के पास पर्याप्त धनराशि जमा करनी चाहिए , ताकि कम से कम 9.5.2003 के आदेश में सूचीबद्ध निगमों के कर्मचारियों को उनका वेतन भुगतान किया जा सके।

7. इन आई.ए. का बिहार राज्य द्वारा प्रतिशपथपत्र दायर करके विरोध किया गया। झारखंड राज्य, जिसे एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया था , ने भी अपना जवाबी हलफनामा दायर किया जिसकी पुष्टि JHALCO रांची के प्रबंध निदेशक, बिनोद कुमार वर्मा ने की। झारखंड राज्य द्वारा लिया गया रुख यह था कि भालको अभी भी बिहार राज्य के नियंत्रण में था और भालको के स्थान पर, झालको के नाम से जाना जाने वाला एक नया निगम 22.3.2002 को कंपनी रजिस्ट्रार, झारखंड द्वारा शामिल और पंजीकृत किया गया था। संक्षेप में, यह रुख अपनाया गया कि झालको का भालको से कोई लेना -देना नहीं है और इसे झालको का उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता। भारत संघ ने एक हलफनामा भी भी दायर किया था, जिसमें यह बताया गया था कि बिहार राज्य द्वारा 18 कंपनियों के संबंध में समापन आवेदन पहले ही दायर किए जा चुके हैं , और इसे देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा धारा 65 के तहत कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं थी। यह भी बताया गया कि 8 कंपनियाँ केवल बिहार के क्षेत्रों के भीतर ही संचालित होती हैं और इस प्रकार, इसके विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह भी बताया गया कि 4 कंपनियों के संबंध में जो बिहार और झारखंड राज्य के दोनों क्षेत्रों में काम कर रही थीं , संपत्ति और देनदारियों के विभाजन के लिए एक निर्देश पहले ही जारी किया गया था। ऐसी ऐसी कंपनियों के संबंध में यह बताया गया कि वे बिहार राज्य और झारखंड राज्य में अंतर-राज्य निगम के रूप में कार्य करना जारी रखेंगी। केंद्र सरकार द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए एक समिति का भी गठन किया गया था , जिसमें मुख्य सचिव, बिहार या उनके नामित व्यक्ति और मुख्य सचिव , झारखंड या उनके नामित व्यक्ति शामिल थे। बिहार राज्य ने यह रुख अपनाया कि भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत निगमित वैधानिक निगमों कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने का राज्य

का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने दिनांक 13.1.2005 को एक विस्तृत आदेश पारित किया। इसने सबसे पहले बिहार राज्य द्वारा अपनाए गए रुख पर अपना असंतोष व्यक्त किया और फिर निम्नानुसार टिप्पणी की:

”यह सच है, जैसा कि झारखंड राज्य की ओर से तर्क दिया गया है कि झालको नामक एक नया निगम अस्तित्व में आया है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि झारखंड राज्य ने स्वयं भालको के कर्मचारियों को विकल्प दिया है, जो कर्मचारी रोजगार का विकल्प चुनते हैं, उनके आमेलन का आदेश शीघ्र और तारीख से छः सप्ताह से ज्यादा न होने वाले समय के भीतर पारित किया जा सकता है। संबंधित कर्मचारियों को इस स्तर पर कोई अण्डरटेकिंग दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रश्न कि क्या झारखंड राज्य भालको के कर्मचारियों को कोई भी वेतन और अन्य परिलब्धियाँ देने के लिए उत्तरदायी है, एक ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय उचित कार्यवाही में किया जाएगा।”

न्यायालय ने आगे यह भी कहा:

”हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने बिहार और झारखंड राज्यों को उपरोक्त निर्देश इस आधार पर जारी नहीं किए हैं कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं, बल्कि इस आधार पर कि यह कर्मचारियों का मानवाधिकार है और अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार भी है जिसकी रक्षा करने के लिए राज्य बाध्य हैं। इस न्यायालय द्वारा 9.5.2003 को जो निर्देश जारी किए गए हैं और जो यहां जारी किए जा रहे हैं, वे संबंधित कर्मचारियों के मानव और मौलिक अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए हैं और वेतन के बकाया के उनके कानूनी अधिकार को लागू करने के माध्यम से नहीं। संबंधित कर्मचारियों या कामगारों को देय वेतन की राशि पर निस्संदेह उचित कार्यवाही में निर्णय लिया जाएगा। हालाँकि निर्देश जारी किए जाते हैं जो उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। निस्संदेह, इन निर्देशों के अनुसार न्यायमूर्ति उदय सिन्हा समिति द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि उचित रूप से जमा की जाएगी।”

इस प्रकार आई.ए. नं. 7, 9 एवं 10 का निस्तारण किया गया।

8. हालाँकि इसके बाद, आई.ए. नं. 11 न्यायालय द्वारा आई.ए. नं. 7, 9 और 10 में पारित आदेश दिनांक 13.1.2005 में संशोधन के लिए दायर किया गया था। एक और आई.ए. नंबर 13, जो दिनांक 13.1.2005 के आदेश के स्पष्टीकरण हेतु दायर किया गया

था। JHALCO की ओर से आई.ए. नंबर 11 में एक हलफनामा दाखिल किया गया और यह निर्देश दिया गया कि स्वीकृत पदों , भरे हुए पदों और शेष का विवरण रिकॉर्ड पर रखा जाए। 11.9.2006 को, आईए संख्या 8 और 11 पर एक और आदेश पारित किया गया। आदेश दिनांक 3.11.2006 द्वारा, झारखंड राज्य को स्थिति रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था जो पहले ही दायर किया गया था। इसके बाद मामले को समय-समय पर स्थगित किया जाता रहा। अंततः, 16.7.2007 को एक आदेश पारित किया गया, जहां सबसे पहले, न्यायालय ने उन कर्मचारियों का खर्च वहन करने के लिए राज्य को वही मानवीय निर्देश जारी किए जो गंभीर रूप से बीमार थे और जहां तक आई.ए. नंबर 11 सन् 2005 का संबंध था, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

”झारखंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिन्हा ने कहा है कि इस न्यायालय के दिनांक 13.1.2005 के आदेश के अनुसार 398 श्रमिकों में से से जो भालको के साथ काम कर रहे थे और जिन्हें इयूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था तीन सप्ताह के भीतर, केवल 302 आये और उन्हें समाहित कर लिया गया है। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अवशोषण का आदेश इस तथ्य के बावजूद पारित किया गया था कि 158 लोगों को अधिशेष पाया गया है। मामले के इस दृष्टिकोण में विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जो लोग उपर्युक्त अवधि के भीतर उनके अवशोषण के लिए उपस्थित नहीं हुए उन्हें समाहित करने का निर्देश इस न्यायालय के दिनांक 13.1.2005 के आदेश के अनुसार नहीं दिया जा सकता है।

विद्वान अधिवक्ता श्री अजित कुमार सिन्हा के इस कथन को ध्यान में रखते हुए कि 158 व्यक्ति अधिशेष हैं, हमारी राय है कि जो लोग नियत तिथि पर इयूटी पर नहीं आए हैं वे इस मामले में उनके लिए विधि में उपलब्ध उपचारों की तलाश कर सकते हैं। हमें उनके अवशोषण के संबंध में कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

आई.ए. नं. 11 तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

आई.ए. नं. 8 हस्तक्षेप के लिए बल नहीं दिए जाने के कारण खारिज किया गया।”
गया।”

9. यह कथन स्पष्ट रूप से गलत था क्योंकि 302 कर्मचारियों का समायोजन स्पष्ट रूप से न्यायालय के आदेश दिनांक 13.1.2005 के अनुसरण में नहीं किया गया था। वास्तव में , भालको के तत्कालीन कर्मचारियों के अवशोषण के लिए वे विज्ञापन

न्यायालय के आदेश दिनांक 13.1.2005 से बहुत पहले जारी किए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 13.1.2005 के आदेश के बाद , तत्कालीन भालको कर्मचारियों द्वारा लगभग 216 आवेदन दायर किए गए थे। इन 216 कर्मचारियों में से 5 अधिकारी 31 तृतीय श्रेणी कर्मचारी और 180 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। इसलिए यह स्पष्ट है कि आई.ए. आई.ए. क्रमांक 11 पर आदेश पारित करते समय इस न्यायालय को दो कारकों के बारे में अंधेरे में रखा गया था। पहला यह कि विज्ञापन दिनांक 13.1.2005 के आदेश से पहले ही ही दिए जा चुके थे और दूसरा यह कि दिनांक 13.1.2005 के आदेश के अनुपालन में कुछ भी नहीं किया गया था , सिवाय इसके कि 216 कर्मचारियों के नए आवेदन JHALCO द्वारा स्वीकार कर लिए गए थे और उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।

10. 21.9.2007 को फिर से, न्यायालय ने राज्य के अधिवक्ता को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

11. इसी पृष्ठभूमि पर वर्तमान आई.ए. नं. 21 दाखिल किया गया है। न्यायालय ने आई.ए. नंबर 21 पर नोटिस जारी किया , जिसे झारखंड राज्य के अधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिन्हा ने स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिनांक 12.11.2007 द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया। अंततः , 13.12.2007 को, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया

“पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद , हमारी राय है कि झालको के अधिवक्ता द्वारा हमारे सामने दिए गए एक बयान से पूर्ववर्ती भालको के कर्मचारियों की स्थिति उत्पन्न हो गई है , जिससे राज्य अब बचना चाहता है , हमारी राय है कि बिहार राज्य और झारखंड राज्य के सचिवों और भालको और झालको के प्रबंध निदेशकों को संबंधित कर्मचारियों के अवशोषण के संबंध में बातचीत करनी चाहिए और इस न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो केन्द्र सरकार के उपयुक्त विभाग का हस्तक्षेप भी लिया जा सकता है।

मामले को 31.1.2008 को सूचीबद्ध करें।

झारखंड राज्य के सिंचाई विभाग के सचिव और झालको के प्रबंध निदेशक भी उस तिथि पर हमारे समक्ष उपस्थित रहेंगे।”

12. जब मामला 31.1.2008 को उठाया गया , तो दो उत्तर शपथ पत्र दायर किए गए थे। JHALCO के प्रबंध निदेशक ने प्रारंभिक उत्तर में विशेष रूप से कहा कि 13.1.2005 13.1.2005 के आदेश के बाद दायर किए गए पहले के हलफनामों में दिखाई गई स्थिति

रिपोर्ट वास्तव में 13.1.2005 से पहले की अवधि की थी, हालांकि यह बाद की अवधि से संबंधित होना बताया गया था। निम्नानुसार बिना शर्त माफी मांगी गई:

"राज्य अपने अधिवक्ता के माध्यम से बिना शर्त माफी मांगता है क्योंकि इसका उद्देश्य केवल 13.1.2005 से पहले का उल्लेख करना था न कि 13.1.2005 के अनुसार।"

बात वहीं रह गई। यह तथाकथित पैरावाइज़ उत्तर कुछ भी नया संदेश नहीं देता प्रतीत होता है। हालाँकि, पैराग्राफ 9 में, यह कहा गया था कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.8.2004 के अनुसरण में, भारत सरकार ने पत्र संख्या 12025/24/2004-एसआर दिनांक 13.9.2004 को निर्णय लिया था कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 65 के संदर्भ में भालको बिहार सरकार के नियंत्रण में रहेगा। इसलिए, उस पैराग्राफ में यह दलील दी गई थी कि भालको और झालको दो अलग-अलग निगम थे जिनके बीच परस्पर निर्भरता का कोई संबंध नहीं था। केवल इसी आधार पर अंततः प्रार्थना की गई कि आई.ए. नं. 21 को निरस्त किया जाना चाहिए।

14. हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि आई.ए. संख्या 11 के अनुसरण में उक्त रिपोर्ट दाखिल करने में और इस न्यायालय के समक्ष गंभीर बयान देते हुए कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.1.2005 के अनुसरण में 302 कर्मचारियों को पहले ही समायोजित किया जा चुका है एक स्पष्ट रूप से भ्रामक और गलत बयान दिया गया था, लेकिन जिसके लिए यह न्यायालय आई.ए. नं. 11 पर दिनांक 16.7.2007 का आदेश पारित नहीं करता। हम अपनी घबराहट व्यक्त करते हैं। हमें यह भी कहना चाहिए कि उस गंजे माफी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं जिसे हम पहले ही ऊपर उद्धृत कर चुके इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि राज्य सरकार की ओर से उसके स्थायी वकील द्वारा ऐसा बयान कैसे जारी किया गया। यह स्पष्ट है कि राज्य ने स्वयं को कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने का केवल एक घटिया प्रयास किया।

15. राज्य ने एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया। अतिरिक्त हलफनामे में, हालांकि यह दोहराया गया कि 17.1.2008 को रांची में संबंधित सचिवों और प्रबंध निदेशकों निदेशकों के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रासंगिक तथ्यों और मुद्दों पर चर्चा की गई थी। हलफनामे में एक बार फिर 302 कर्मचारियों के पूर्ववर्ती अवशोषण के बारे में कहा गया है, और आगे कहा गया है कि आज की तारीख में, भालको में 216 कर्मचारी बचे हैं जिन्हें अब तक समायोजित नहीं किया गया है। तब यह बताया गया कि JHALCO के पास पहले से ही 152 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का अधिशेष था और यदि 216 कर्मचारियों को और शामिल करने का निर्देश दिया गया, तो JHALCO एक बीमार कंपनी

बन जाएगी। हलफनामे में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा 13.9.2004 को आदेश के कारण प्रारंभिक जिम्मेदारी भालको की है। हलफनामे में यह भी दोहराया गया कि बिहार सरकार और भालको के प्रबंध निदेशक ने 13.9.2004 के इस आदेश को स्वीकार नहीं किया और गृह मंत्रालय के खिलाफ विरोध जताया था और कहा था कि भालको के सभी कर्मचारियों को झालको में समाहित कर लिया जाना चाहिए। इसके बाद हलफनामे में घटनाओं का कुछ कालक्रम दिया गया है , जिसमें दिखाया गया है कि JHALCO को कैसे अस्तित्व में लाया गया। यह स्वीकार किया गया कि झालको ने भालको के नियमों और विनियमों को अपनाया और अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संस्थानों से कुछ सहायता प्राप्त की। साथ ही यह आशा व्यक्त की गई कि आवश्यकतानुसार ही भालको के कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी। पुनः उन दो विज्ञापनों का संदर्भ दिया गया जिनके द्वारा भालको के कर्मचारियों को अवशोषण के लिए आवेदन करने का अवसर दिया गया था। यह भी बताया गया कि मस्टर-रोल कर्मचारियों, सरकारी विभाग में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों और कटे-फटे दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले कर्मचारियों को JHALCO द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। इसके बाद इस न्यायालय के 9.5.2003 के पहले आदेश का संदर्भ दिया गया और आगे बताया गया कि 13.9.2004 के आदेश द्वारा, राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि आज की तारीख में , भालको बिहार सरकार के नियंत्रण में रहेगा। पैरा (प) में एक बहुत ही रोचक कथन दिया गया है , जो इस प्रकार है:

”इसलिए केंद्र सरकार के आदेश दिनांक 13.9.2004 के बाद , झारखंड राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी अपने आदेश संख्या 2580 दिनांक 29.12.2001 में पहले की गई तकनीकी त्रुटि को ठीक करने के अपने पहले के निर्णय को रद्द करने की मांग की। अक्टूबर 2004 में विभागीय मंत्री द्वारा इस प्रस्ताव मंजूरी दे दी गई थी। हालांकि, राज्य में चुनाव के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद कैबिनेट ने 4.4.2005 की बैठक में अपने पूर्व निर्णय को संशोधित किया और डब्ल्यूआरडी, झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 1283 दिनांक 26.4.2005 के तहत आदेश जारी किया गया।”

16. इसके बाद इस न्यायालय के दिनांक 13.1.2005 के आदेश में संशोधन के लिए एक आवेदन का संदर्भ दिया गया, जो कथित तौर पर 15.2.2005 को झारखंड राज्य द्वारा दायर किया गया था। इसके अलावा , झारखंड राज्य द्वारा दिनांक को दायर प्रत्युत्तर हलफनामे का भी हवाला दिया गया , जिसमें शेष भालको कर्मचारियों को शामिल करने में असमर्थता दिखाई गई थी। इस अतिरिक्त हलफनामे के पैराग्राफ 8

(ए) और 8 (बी) में सुझाव दिया गया है कि झालको ने भालको के नियमों और विनियमों विनियमों को अपनाया है, और झालको को वित्तीय संस्थानों से सहायता प्राप्त होगी। तब यह माना गया कि JHALCO को शुरू करने और चलाने के लिए अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता थी। चूंकि भालको कर्मचारी बेकार बैठे थे , इसलिए मानवीय आधार पर उन्हें एक अवसर दिया गया। पुनः 302 समाहित कर्मचारियों के संबंध में वही तालिका प्रस्तुत की गई। फिर यह दोहराया गया कि पहले से ही समाहित अतिरिक्त कर्मचारियों के कारण JHALCO की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं किया जा सका। पैरा 8 (ई) में डब्ल्यूआरडी अधिसूचना संख्या 1283 दिनांक 26.4.2005 द्वारा जारी झारखंड सरकार के निर्णय का संदर्भ दिया गया था और इस निर्णय के अनुसरण में 8.8.2005 को JHALCO की वित्तीय स्थिति और उसके कार्य प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई। यह पैरा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस प्रकार है:

”(ई) डब्ल्यूआरडी अधिसूचना संख्या 1283 दिनांक 26.4.2005 द्वारा जारी झारखंड सरकार के निर्णय के अनुसार , झालको के निदेशक मंडल ने झालको की वित्तीय स्थिति के साथ-साथ उसके कार्य प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए दिनांक 8.8.2005 को एक बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया निगम जिस कार्य को निष्पादित कर रहा है उसकी प्रकृति को देखते हुए कर्मचारियों की संख्या में कटौती करें , क्योंकि सभी योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित योजनाओं के लाभार्थी द्वारा किया जाता है और योजना के पूरा होने के बाद लाभार्थी समिति को सौंप दिया जाता है। निदेशक इस प्रकार हैं:

क्र.सं. पद की श्रेणी कुल कार्यरत कर्मचारी

(i) अधिकारी	78
(ii) तृतीय श्रेणी	44
(iii) चतुर्थ श्रेणी	92
कुल =	214

(च) निगम द्वारा निष्पादित कार्य की प्रकृति को देखते हुए झालको के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत संख्या को ध्यान में रखते हुए , इसकी आवश्यकता की तुलना में झालको में पहले से ही कार्यरत भालको कर्मचारियों का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	पद की श्रेणी	कुल स्वीकृत पद	कुल कार्यरत कर्मचारी	शेष
(I)	अधिकारी	78	14	(-) 64
(ii)	तृतीय श्रेणी	44	44	Nil
(iii)	चतुर्थ श्रेणी	92	244	(+) 152

उपरोक्त तुलनात्मक विवरण से ही पता चलता है कि भालको चतुर्थ श्रेणी के 152 अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है , जिसके संबंध में झारखंड सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र दायर किया गया है।

(छ) शेष भालको कर्मचारी लगभग 216 हैं। याचिकाकर्ता (भालको कर्मचारी) द्वारा दायर आई.ए.-21 के अनुसार इन कर्मचारियों की श्रेणीवार स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	पद की श्रेणी	शेष भालको कर्मचारी
(i)	अधिकारी	05
(ii)	तृतीय श्रेणी	31
(iii)	चतुर्थ श्रेणी	180
	कुल =	216

(ज) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है , भालको के शेष 216 कर्मचारियों में तृतीय श्रेणी के 31 कर्मचारी हैं जिनकी झालको में आवश्यकता नहीं है और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 180 हैं जबकि झालको ने पहले ही भालको के 152 अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लगा रखा है।

(प) ऑडिट रिपोर्ट 2005-06 के अनुसार, JHALCO पहले से ही 3.16 करोड़ घाटे में चल रही है।

(जे) झालको कर्मचारियों का वार्षिक वेतन लगभग 3.60 करोड़ है, जबकि झालको द्वारा अर्जित लाभ लगभग एक करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए JHALCO कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए WPD झारखंड राज्य से 2.60 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

17. फिर आगे के पैराग्राफ में यह प्रस्तुत किया गया कि JHALCO झारखंड सरकार की मदद से वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनने की कोशिश कर रहा था। यह भी बताया गया कि पूर्ववर्ती भालको में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी लगे हुए थे और संगठन अपने कर्मचारियों का बोझ नहीं उठा सकता था। इसलिए , यह दोहराया गया कि शेष भालको कर्मचारियों को लेने के अनुमान को अनिश्चित वित्तीय स्थिति और अतिरिक्त कर्मचारियों के प्रकाश में देखा जाना चाहिए। इसलिए यह दोहराया गया कि अगर उन कर्मचारियों को लिया गया तो झालको भी एक बीमार कंपनी बन जायेगी। बाकी पैराग्राफों में , भालको के परिसमापन से संबंधित अन्य तथ्यों के साथ ही दिनांक 17.1.2008 की बैठक की विफलता जो इस न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था, का उल्लेख किया गया था।

18. हमने जानबूझकर झारखंड राज्य और झालको की ओर से दो हलफनामों का उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया है कि झालको और राज्य समयसमय पर अपना अपना रुख बदल रहे हैं। कई बार उनके रुख विरोधाभासी और समझ से बाहर हो गए हैं। यह पहले ही नोट किया जा चुका है कि JHALCO बहुत पहले 29.12.2001 को अस्तित्व में आया था , क्योंकि झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद BHALCO का संचालन क्षेत्र झारखंड की सीमा के भीतर आ गया था। कैबिनेट नोट दिनांक 9.1.2002 जो रिट याचिकाकर्ता द्वारा आईए. संख्या 11 सन् 2005 के साथ दायर किया गया था जो स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी कि भालको को झालको के रूप में चलाया जाना चाहिए। 2003 में, JHALCO ने BHALCO कर्मचारियों के अवशोषण के लिए दो विज्ञापन दिए और बाद में भी, यह स्वीकार किया गया कि JHALCO JHALCO को BHALCO के अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता थी। इन विज्ञापनों के अनुसरण में, भालको के सभी कर्मचारी नियमित होने के लिए आवेदन कर सकते थे बशर्ते बशर्ते उनके आवेदन सही पाए गए हों। तदनुसार , लगभग 302 कर्मचारियों को समाहित किया गया। दूसरों के आवेदन अस्वीकार कर दिए गए और कुछ अन्य ने आवेदन ही नहीं नहीं किया था शायद इस शर्त के कारण कि ऐसे कर्मचारियों को अवैतनिक वेतन के अपने अपने पहले के दावों को छोड़ना पड़ा। जिस समय विज्ञापन जारी किए गए थे , उस समय सभी कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए किसी भी न्यायालय के आदेश के माध्यम से कोई बाध्यता नहीं थी और यह केवल एक मानवीय विचार हो सकता था जिससे उक्त

विज्ञापन जारी किए गए। यह नहीं भुलाया जा सकता कि झालको के पास कोई प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नहीं था और इसलिए, झालको को झालको के अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता थी। इसलिए यह कदम केवल BHALCO के नामकरण को बदलने और JHALCO JHALCO के समान जारी रखने के लिए था। ऐसा लगता है कि इन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करना एक गैर-कारक था और इसलिए, JHALCO दोहरा लाभ प्राप्त करना चाहता था, अर्थात्, उसे सभी अनुभवी कर्मचारी मिल सकते थे और दूसरा वह भी दायित्व दायित्व का सामना किए बिना उनके वेतन भुगतान का। यह याद रखना चाहिए कि यह सब इस न्यायालय के दिनांक 9.5.2003 के आदेश के मद्देनजर था, जिसमें इस न्यायालय ने बिहार राज्य को निगमों के कर्मचारियों को वेतन के वितरण के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि जमा करने के लिए कहा था। और जरूरतमंद कर्मचारियों को तदर्थ आधार पर धनराशि वितरित करने का भी निर्देश दिया था। कोर्ट ने कंपनियों की संपत्ति और देनदारियों की जांच के लिए एक समिति बनाने का भी निर्देश दिया था। इसलिए जब जब विज्ञापन 7.8.2003 की कट-ऑफ तारीख के साथ जारी किए गए, तो श्रमस्व को एक अलग फायदा हुआ। हालाँकि, इसके बाद, इस न्यायालय का दिनांक 13.1.2005 का आदेश आया, जिसके तहत, इस न्यायालय ने JHALCO के अस्तित्व में आने का नोटिस लिया और आगे निर्देश दिया जिन संबंधित कर्मचारियों को समाहित किया जाना था, उन्हें पिछले अवैतनिक वेतन के लिए अपने दावों को छोड़ने का वचन देने की आवश्यकता आवश्यकता नहीं है। तब तक आदेश दिनांक 13.1.2005 की भाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि आमेलन हेतु कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया गया था। शायद इसीलिए इस कोर्ट ने ऐसे कर्मचारियों को छह हफ्ते का वक्त दिया है, जैसा कि पहले के विज्ञापनों में था, केवल वेतन पर अपना दावा छोड़ने वाले कर्मचारी ही आवेदन कर सकते थे, सभी कर्मचारियों ने शायद संख्या को केवल 302 तक सीमित रखते हुए आवेदन नहीं किया था। अब, आदेश दिनांक 13.1.2005 के अनुसरण में, 216 और कर्मचारियों ने आवेदन किया था और वह भी वेतन पर अपना दावा छोड़े बिना। संभवतः इसी कारण दिनांक 8.8.2005 की बैठक में झालको की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने, कर्मचारियों की संख्या कम करने तथा कुल कर्मचारियों की संख्या 214 तक सीमित करने का निर्णय लिया गया। वास्तव में, यदि पैराग्राफ ए (एफ) अतिरिक्त हलफनामे को देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि हालांकि 152 अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, फिर भी 64 अधिकारियों की आवश्यकता थी, क्योंकि 78 अधिकारियों की कुल स्वीकृत शक्ति के मुकाबले केवल 14 अधिकारी कार्यरत थे। कर्मचारियों को कम करने और कर्मचारियों की कुल संख्या 214 तक सीमित करने की यह कवायद इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.1.2005 के मद्देनजर एक जानबूझकर की गई कवायद प्रतीत होती है, और

उस आदेश का भी उसकी वास्तविक भावना से पालन नहीं किया गया , जो अंततः याचिकाकर्ताओं को आईए. नंबर 11 दाखिल करने की आवश्यकता है। अतिरिक्त शपथ पत्र के पैराग्राफ ए(एफ) में दिए गए आंकड़े भी भ्रामक हैं। यदि ठीक से गणना की जाए तो कुल स्वीकृत संख्या 214 के मुकाबले 302 कर्मचारी कार्यरत थे। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि केवल 88 अतिरिक्त कर्मचारी कार्यरत थे और वह भी दिनांक 8.8.2005 के निर्णय से पहले। इसलिए अतिरिक्त कर्मचारियों के रूप में 152 का आंकड़ा स्पष्ट रूप से भ्रामक है। JHALCO द्वारा कर्मचारियों की कटौती को उचित ठहराने के लिए न तो कोई स्पष्टीकरण है, न ही कोई आँकड़े। आखिरकार क्षेत्र या गतिविधियों में कोई कटौती नहीं की गई, कम से कम किसी ने हमारे सामने गुहार नहीं लगाई , ऐसे में JHALCO के कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने का निर्णय न तो उचित , न ही उचित और न ही उचित प्रतीत होता है और केवल बाहर निकलने के लिए प्रतीत होता है इस न्यायालय के दिनांक 13.1.2005 के आदेश की कठोरता। जो भी हो , उसके बाद हुई चर्चाओं के मद्देनजर, हम आवेदकों के पक्ष में कोई भी आदेश पारित करने की स्थिति में नहीं हैं , भले ही रिक्तियों के अस्तित्व के संबंध में उनकी दलीलें स्वीकार कर ली गई हों।

19. हालाँकि वित्त की एक बड़ी समस्या है। अतिरिक्त हलफनामे में दलील दी गयी है कि झालको 2005-06 तक 3.16 करोड़ रुपये घाटे में चल रही थी। आज की तारीख में में इसका वार्षिक वेतन 3.60 करोड़ है और इसने वित्तीय वर्ष 2008-09 के भुगतान के लिए झारखंड राज्य से 2.60 करोड़ रुपये की मांग की है। हालाँकि, हलफनामे में वेतन के बकाया के कारण बिहार राज्य द्वारा किए जाने वाले योगदान के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

20. जब हम बिहार राज्य की प्रतिक्रिया देखते हैं , तो बिहार सरकार के सचिव द्वारा झारखंड सरकार के सचिव को दिनांक 22.1.2001 के पत्र के संदर्भ को छोड़कर , जिसमें सिफारिश की गई थी कि झालको के सभी कर्मचारियों को बिना किसी शर्त के झालको में समाहित किया जाना चाहिए , इससे अधिक कुछ भी प्रतीत नहीं होता। बिहार राज्य की ओर से लिखित दलीलों के नाम पर, केवल इतना कहा गया है कि चूंकि झालको झारखंड राज्य में स्थित एक निगम था और इसका संचालन क्षेत्र भी झारखंड राज्य में ही था , इसलिए धारा 47 के तहत (1) और बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 56 के अनुसार, झालको अपनी सभी देनदारियों और संपत्तियों के साथ झारखंड सरकार का एक निगम है। बिहार राज्य ने फिर दोहराया है कि झालको को बिहार राज्य की संपत्ति मानने का केंद्र सरकार का निर्णय और झालको के परिसमापन के लिए कदम उठाने के लिए दिनांक 13.9.2004 के पत्र के माध्यम से दिया गया निर्देश सही निर्णय

नहीं है, और यह इस पर पुनर्विचार करने के लिए पत्र लिखा था। हम इस बात पर आश्चर्य आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि बिहार राज्य द्वारा इतना अड़ियल रुख कैसे अपनाया गया। किसी भी कोण से देखा जाए, तो बिहार राज्य द्वारा इस विशिष्ट दलील पर इस दायित्व से पूरी तरह से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है कि भालको अब झालको बन गया है। यह मुद्दे का अत्यधिक सरलीकरण होगा। यह इस तथ्य से अलग है कि भालको के मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन में बिहार के छह जिलों का उल्लेख है जो इसके संचालन क्षेत्र क्षेत्र के रूप में बिहार राज्य में बने रहे। हमने दिनांक 13.9.2004 के आदेश को ध्यान से देखा है जो बिहार राज्य पर बाध्यकारी है। उस आदेश के द्वारा , केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि बिहार राज्य सरकार भालको के संबंध में परिसमापन शुरू करेगी। यदि ऐसा है, तो आवश्यक तर्क के अनुसार , बकाया वेतन का भुगतान करने का दायित्व बिहार राज्य का है, जिसे उसे पूरा करना होगा।

21. हालाँकि हमें बताया गया है कि पिछले वेतन के साथसाथ अवशोषण का दावा दावा करने वाले कर्मचारियों द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका लंबित इसलिए हम अंतिम निर्देश देने से बचेंगे, इसलिए हम सीधे इस न्यायालय के समक्ष दायर दायर जनहित याचिका में श्रम विवाद से निपटना नहीं चाहते हैं। बेहतर होगा कि उक्त रिट रिट याचिका में लंबित सभी प्रश्नों पर यथाशीघ्र अंतिम निर्णय लिया जाए।

इस मामले का एक और पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता . 13 जनवरी, 2005 के हमारे आदेश को लागू करने का तरीका अदालत की अवमानना अधिनियम , 1970 के तहत अवमानना की कार्यवाही शुरू करना होगा। ऐसी कार्यवाही , जैसा कि सर्वविदित है अंतिम उपाय के माध्यम से शुरू की जानी चाहिए।

सुशीला राजे होल्कर बनाम अनिल काक (सेवानिवृत्त) [2008(7) स्केल 484] में, इस न्यायालय ने कहा:

"14. न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्यवाही का एक गंभीर परिणाम होता है। क्या कथित अवमाननाकर्ता ने सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया है या उसके परिणामस्वरूप होने वाले सिविल बुरे परिणामों की परवाह नहीं की है , इसकी सख्त जांच की आवश्यकता है। उक्त प्रयोजन के लिए , न्यायालय के आदेश को संपूर्णता में पढ़ने की अनुमति हो सकती है। आदेश के प्रभाव और अभिप्राय को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

जबकि अदालत हमेशा उत्साहपूर्वक अपने आदेश को लागू करेगी लेकिन केवल तकनीकता अवमाननाकर्ता को दंडित करने का आधार नहीं होनी चाहिए।

अवमानना की कार्यवाही अत्यंत सावधानी के साथ शुरू की जानी चाहिए। इसका प्रयोग उचित देखभाल और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की न्यायालय की शक्ति कोई अनियंत्रित या असीमित शक्ति नहीं है। यह प्रकृति में एक नियंत्रित शक्ति और प्रतिबंधात्मक है (देखें रि: पीसी सेन [(1969) 2 एससीआर 649] और झरेश्वर प्रसाद पॉल और अन्य बनाम तारक नाथ गांगुली और अन्य [(2002) 5 एससीसी 352])।

इस प्रकार, किसी अवमाननाकर्ता को केवल तभी दंडित किया जा सकता है जब अपमानजनक आचरण का स्पष्ट मामला बनाया गया हो।”

केवल इसलिए कि हमारे सामने एक गलत बयान दिया गया था जिसके संबंध में हमने पहले अपनी टिप्पणियाँ की थीं, हमारी राय में, हमारे सामने दोषी अधिकारियों की शुरुआत और परिणामी सजा से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए, हम स्वयं को ऐसा करने से रोकते हैं।

22. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निर्देश देते हैं:

(ए) झारखंड उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि उसके समक्ष लंबित रिट याचिका का निपटारा यथाशीघ्र और, यदि संभव हो तो, तारीख से छह सप्ताह के भीतर करे। यदि उच्च न्यायालय को उपरोक्त अवधि के भीतर मामले का निपटारा करना मुश्किल लगता है, तो वह अंतरिम आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उपयुक्त और उचित समझे। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि आवेदक पिछली तारीख तारीख से झालको की सेवाओं में समाहित होने के हकदार हैं तो वह पक्षकारों के बीच इक्विटी को समायोजित करने के लिए ऐसा आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा जो वह उपयुक्त और उचित समझे। यह स्पष्ट किया गया है कि अंतिम अवशोषण , पिछले वेतन और उसे भुगतान करने के दायित्व का प्रश्न उक्त रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(बी) प्रबंध निदेशक, भालको और प्रबंध निदेशक , झालको के साथ-साथ बिहार सरकार और झारखंड सरकार के सचिव भी तारीख से एक महीने के भीतर बैठक करेंगे और देय वेतन के बकाया के संबंध में दायित्व पर निर्णय लेंगे और उसका आकलन करेंगे। पहले से ही आमेलित और आमेलित किए जाने वाले कर्मचारियों को , और

कर्मचारियों को भुगतान के तरीके आदि, यदि कोई हो, के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए निर्णय की तारीख से एक सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय को इसकी रिपोर्ट दें , ताकि देनदारी को कम किया जा सके। झालको की आय उस सीमा तक कम हो जाएगी।

(सी) केंद्र सरकार यह देखने के लिए तत्काल कदम उठाएगी कि उसके द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2004 में दिए गए निर्देशों का बिहार राज्य द्वारा अनुपालन किया गया है। अंतरिम आवेदन तदनुसार निपटाया जाता है। अपील निस्तारित की गई।

यह इस निर्णय के अनुवाद की शब्दशः सही जांच/ सत्यापन है।

(मिथिलेश पाण्डेय)